

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1975

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

मणिपुर के सशस्त्र समूहों के साथ शांति वार्ता हेतु संवादी

1975. श्री रोनाल्ड सपा लाउ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनाइटेड पीपल फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के साथ कार्रवाई को निलंबित रखने (एसओओ) पर हस्ताक्षर करने के साथ वर्ष बीतने के बाद भी भारत सरकार और मणिपुर के जोमी, कुकी और हमार जनजातीय सशस्त्र समूहों के साथ शांति वार्ता के लिए केन्द्र द्वारा संवादी नियुक्त नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और इस मामले पर सरकार की क्या स्थिति है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मणिपुर सरकार और केन्द्रीय सरकार को शामिल करते हुए यूपीएफ और केएनओ के साथ वास्तविक राजनीतिक त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करने की कोई योजना है, यदि हां, तो इस संबंध में बनायी गई रुपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रियाशील विभिन्न समूहों की मांगों को ध्यान

में रखते हुए, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति की निरंतर रूप से समीक्षा

करती है और मैत्रीपूर्ण तरीके से मुद्दों का समाधान करने के लिए वार्ताकार की नियुक्ति

सहित उपाय करती है। मणिपुर के जोमी, कुकी और हमर जनजातीय सशस्त्र समूहों के

साथ वार्ता आरंभ करने के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है।
